

नरियात तैयारी सूचकांक 2022

प्रलिस के लयि:

[नीतआयोग](#), [प्रतयकष वदशी नवश](#), [प्रौद्योगकी उन्नयन नधियोजना](#), [भौगोलक संकेतक](#)

मेन्स के लयि:

नरियात तैयारी सूचकांक 2022 पर नीतआयोग की रपिर्ट

हाल ही में [नीतआयोग](#) ने [नरियात तैयारी सूचकांक 2022](#) (Export Preparedness Index 2022) शीर्षक से एक रपिर्ट जारी की है ।

नरियात तैयारी सूचकांक 2022:

EPI 2022 भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों की उनकी नरियात तैयारी आधारति रैकगि है । यह एक समग्र सूचकांक है जो 4 स्तंभों और 10 उप-स्तंभों के आधार पर राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों के प्रदर्शन को मापता है:

मुख्य स्तंभ:

नीति:

- नरियात-आयात के लयि रणनीतिक दशा प्रदान करने वाली एक व्यापक व्यापार नीति।

व्यापार पारस्थितिकी तंत्र:

- राज्यों को नविश आकर्षति करने और व्यक्तियों के लयि स्टार्ट-अप शुरू करने हेतु एक सक्रम बुनयादी ढाँचा तैयार करने में मदद के लयि कुशल व्यापार पारस्थितिकी तंत्र ।

नरियात पारस्थितिकी तंत्र:

- नरियात के लयि वशिष्ट कारोबारी माहौल का आकलन ।

नरियात प्रदर्शन:

- यह एकमात्र आउटपुट-आधारति पैरामीटर है जो राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों के नरियात फुटप्रिंट की पहुँच की जाँच करता है ।

उप-स्तंभ:

नरियात प्रोत्साहन नीति:

- राज्य की नरियात प्रोत्साहन नीतिकी गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता ।

संस्थागत ढाँचा:

- व्यापार और नरियात के लयि राज्य के संस्थागत ढाँचे की ताकत और प्रभावशीलता ।

कारोबारी माहौल:

- राज्य में व्यापार करने में सुलभता और नरियातकों के लयि सहायता सेवाओं की उपलब्धता ।

अवसंरचना:

- नरियात के लयि आवश्यक सड़क, पत्तन और हवाई अड्डों जैसे भौतिक बुनयादी अवसंरचनाओं की उपलब्धता ।

परविहन कनेक्टिविटी:

- प्रमुख नरियात बाजारों से राज्य की कनेक्टिविटी ।

नरियात अवसंरचना:

- नरियात के लयि आवश्यक वशिष बुनयादी अवसंरचनाओं की उपलब्धता, जैसे गोदाम और कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ ।

व्यापार समर्थन:

- व्यापार वत्ति, बीमा और अन्य व्यापार-संबंधी सेवाओं की उपलब्धता ।

अनुसंधान एवं वकिस अवसंरचना:

- नए नरियात उत्पादों और सेवाओं को वकिसति करने में मदद हेतु अनुसंधान और वकिस सुविधाओं की उपलब्धता ।

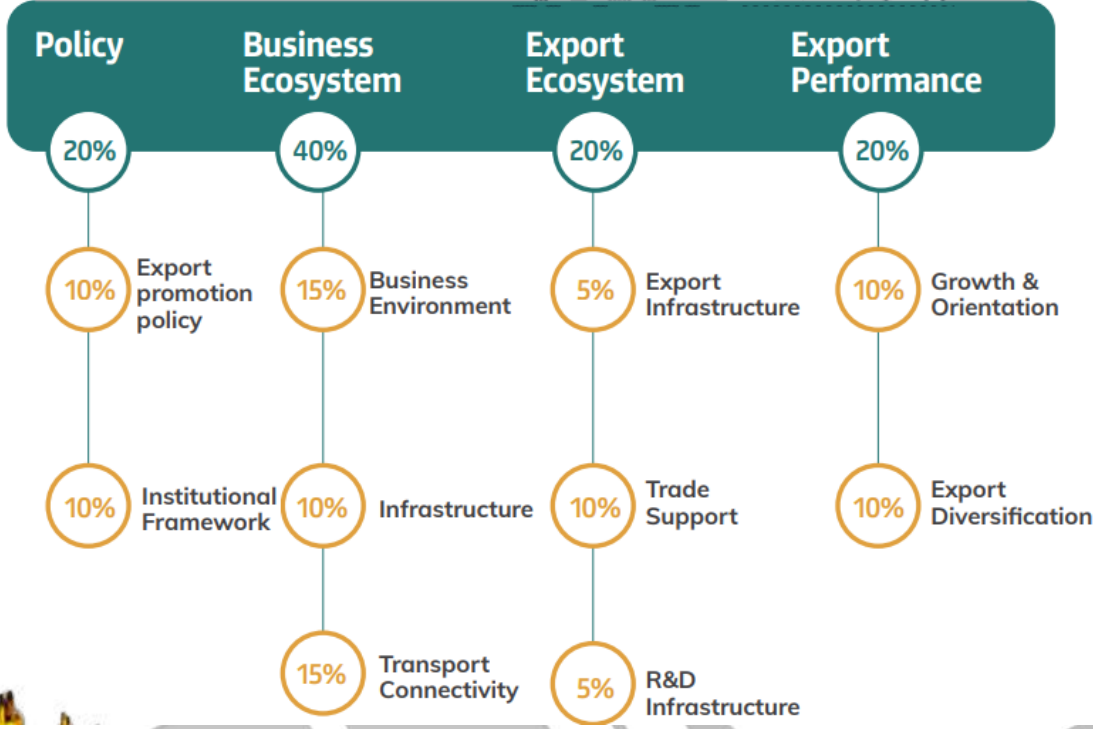
नरियात वविधीकरण:

- वभिन्न क्षेत्रों और बाजारों में राज्य की नरियात वविधिता ।

वकिस उन्मुखीकरण:

- नरियात-आधारित विकास के लिये राज्य की प्रतिबद्धता ।

Export Preparedness Index Framework



EPI 2022 की मुख्य विशेषताएँ:

राज्यों का प्रदर्शन:

■ शीर्ष प्रदर्शक राज्य:

- EPI 2022 में तमलिनाडु शीर्ष पर है, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान है ।
- EPI 2021 (2022 में जारी) में गुजरात शीर्ष स्थान पर था, कति EPI 2022 में तीन अंक नीचे अर्थात् चौथे स्थान पर चला गया है ।
- नरियात मूल्य, केंद्रित नरियात और वैश्विक बाजार फुटप्रिंट सहित नरियात प्रदर्शन संकेतकों के संदर्भ में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते तमलिनाडु ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की ।
- तमलिनाडु ऑटोमोटिवि, चर्म, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे क्षेत्रों में लगातार अग्रणी रहा है ।

■ पहाड़ी/हिमालयी राज्य:

- EPI 2022 में पहाड़ी/हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया है । इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिकिम, नगालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मजोरम का स्थान है ।

	Rank	State	Category	Score
Himalayan	1	Uttarakhand	Himalayan	59.13
	2	Himachal Pradesh	Himalayan	52.25
	3	Manipur	Himalayan	40.77
	4	Tripura	Himalayan	38.30
	5	Sikkim	Himalayan	36.86
	6	Nagaland	Himalayan	33.33
	7	Meghalaya	Himalayan	24.34
	8	Arunachal Pradesh	Himalayan	19.92
	9	Mizoram	Himalayan	16.96

■ **सथलरुद्ध क्षेत्र:**

- EPI 2022 में भूमिसे घरि क्षेत्रों में हरयाणा शीर्ष पर है, यह नरियात क्षेत्र में उसकी तैयारियों को परदरशति करता है।
- इसके बाद तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान है।

	Rank	State	Category	Score
Landlocked	1	Haryana	Landlocked	63.65
	2	Telangana	Landlocked	61.36
	3	Uttar Pradesh	Landlocked	61.23
	4	Punjab	Landlocked	58.95
	5	Madhya Pradesh	Landlocked	55.68
	6	Rajasthan	Landlocked	54.80
	7	Jharkhand	Landlocked	43.91
	8	Assam	Landlocked	43.19
	9	Bihar	Landlocked	41.06
	10	Chattisgarh	Landlocked	39.10

■ **केंद्रशासति प्रदेश/छोटे राज्य:**

- केंद्रशासति प्रदेशों तथा छोटे राज्यों में गोवा EPI 2022 में पहले स्थान पर है।
- जम्मू-कश्मीर, दलिली, अंडमान और नकिोबार द्वीप समूह तथा लद्दाख ने क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा एवं पाँचवाँ स्थान हासलि कयि।

	Rank	State	Category	Score
UT/Small States	1	Goa	UT/Small States	51.58
	2	Jammu and Kashmir	UT/Small States	47.79
	3	Delhi	UT/Small States	47.69
	4	Andaman and Nicobar Islands	UT/Small States	40.65
	5	Ladakh	UT/Small States	31.51
	6	Chandigarh	UT/Small States	31.27
	7	Puducherry	UT/Small States	24.24
	8	Dadra Nagar and Haveli & Daman and Diu	UT/Small States	18.74
	9	Lakshadweep	UT/Small States	11.30

■ वैश्विक अर्थव्यवस्था:

- वर्ष 2021 में वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में कोविड-19 से उबरने के संकेत देखे गए। वस्तुओं की बढ़ती मांग, राजकोषीय नीतियाँ, वैक्सीन वितरण तथा प्रतिबंधों में ढील जैसे कारकों ने पिछले वर्ष की तुलना में **माल व्यापार में 27% की वृद्धि** एवं **सेवा व्यापार में 16% की वृद्धि** में योगदान दिया।
- फरवरी 2022 में **रूस-यूक्रेन युद्ध** ने रकवरी/उगाही को धीमा कर दिया, जिससे **अनाज, तेल तथा प्राकृतिक गैस** जैसे क्षेत्र प्रभावित हुए।
- वस्तुओं के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई तथा सेवा व्यापार वर्ष 2021 की चौथी तमिाही तक महामारी से पूर्व के स्तर पर पहुँच गया।

■ भारत के नरियात रुझान:

- वैश्विक मंदी के बावजूद वर्ष 2021-22 में भारत का **नरियात अभूतपूर्व रूप से 675 बलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया**, जिसमें माल का व्यापार 420 बलियन अमेरिकी डॉलर का था।
- वतित वर्ष 2022 में माल नरियात मूल्य 400 बलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, यह सरकार द्वारा नरिधारति एक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य है, जो **मार्च 2022 तक 422 बलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा**।
 - इस प्रदर्शन के कई कारण थे। वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा विकसित देशों की मांग में वृद्धि ने भारत के व्यापारिक नरियात को बढ़ाने में मदद की।

■ तटीय राज्यों का प्रदर्शन:

- तटीय राज्यों ने वभिन्न संकेतकों में बेहतर प्रदर्शन प्रदर्शति कयिा है, नरियात सूचकांक में शीर्ष छह राज्य तटीय क्षेत्र से आते हैं।
- **तमलिनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा गुजरात** सहति इन राज्यों ने वभिन्न क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन कयिा है एवं अपने भौगोलिक लाभ के कारण राष्ट्रीय नरियात में सकारात्मक योगदान दिया है।

	Rank	State	Category	Score
Coastal	1	Tamil Nadu	Coastal	80.89
	2	Maharashtra	Coastal	78.20
	3	Karnataka	Coastal	76.36
	4	Gujarat	Coastal	73.22
	5	Andhra Pradesh	Coastal	59.27
	6	Odisha	Coastal	58.84
	7	West Bengal	Coastal	53.57
	8	Kerala	Coastal	44.03

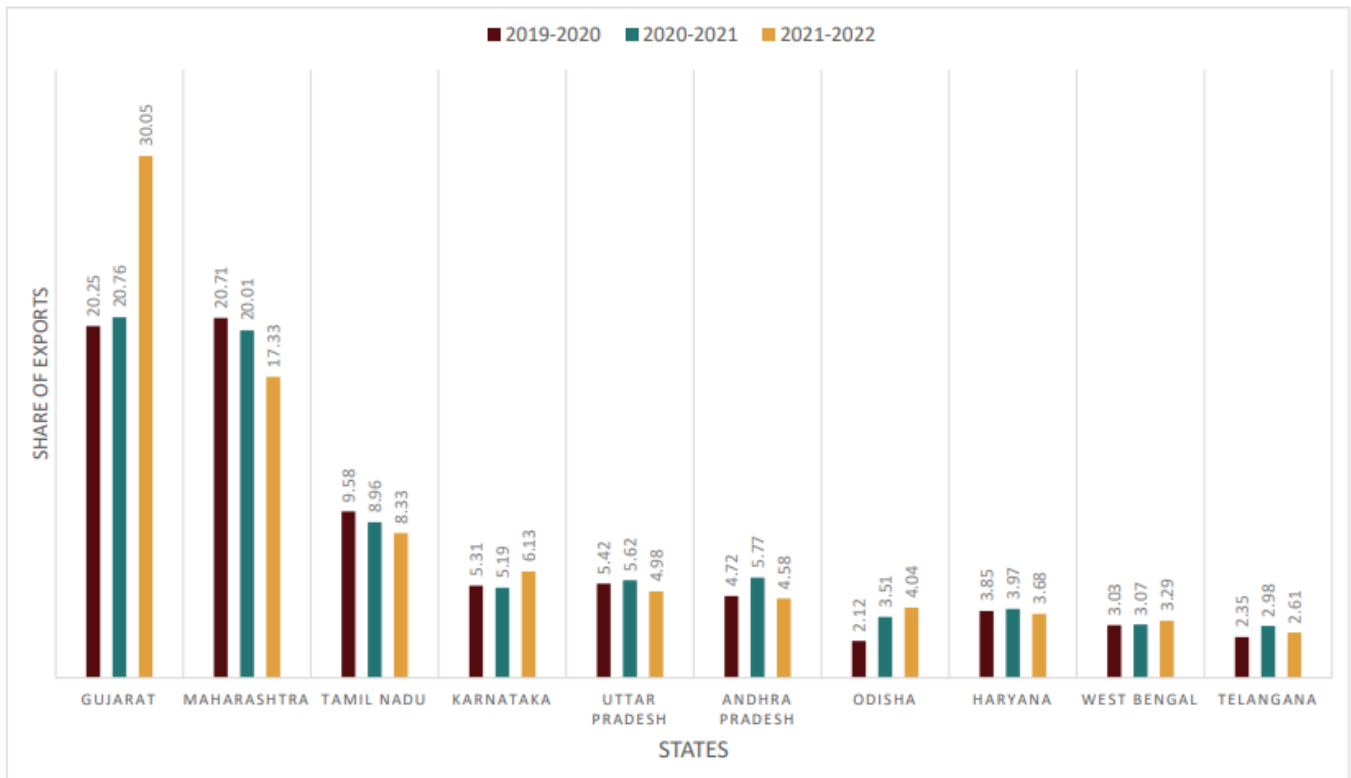
■ स्थल-अवरुद्ध राज्य:

- उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा को छोड़कर, भूमि से घरी राज्यों ने सामान्य रूप से संतोषजनक प्रदर्शन किया है, ये दोनों राज्य सकारात्मक बाहरी कारकों के कारण सामने आए हैं।
- हालाँकि पंजाब और तेलंगाना ने संतोषजनक प्रदर्शन किया है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने अपने क्षेत्रीय लाभों का पूरी तरह से लाभ नहीं उठाया हो, जिसके परिणामस्वरूप समग्र प्रदर्शन औसत रहा है।

■ हिमालयी केंद्रशासित प्रदेश तथा अन्य छोटे राज्य:

- उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा तथा दिल्ली को छोड़कर हिमालयी केंद्रशासित प्रदेश तथा अन्य छोटे राज्यों ने निर्यात सूचकांक में असंतोषजनक प्रदर्शन किया है।
- उनकी निर्यात तत्परता में सुधार के लिये संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तत्काल सुधार की आवश्यकता के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है।

% age Share of Top 10 States in India's Exports Across 3 Years



- नीति पारिस्थितिकी तंत्र एवं अवसंरचना:
 - कई राज्यों ने नरियात-उन्मुख नीति उपायों को अपनाने के साथ नरियात में वृद्धि के लिये आवश्यक कार्रवाईयों की हैं।
 - समरूपि-औद्योगिकि क्षेत्रों, सगिल-वडि क्लीयरेंस तथा नरियात बुनयादी ढाँचे की उपस्थिति ने सकारात्मक कारोबारी परस्थिति निर्माण में योगदान दिया है।
 - देश के 29 राज्यों ने अपने महामारी-पूर्व स्तर से अधिक नरियात में सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की है, जो कि नरियात में वृद्धि का प्रमाण है।
- परविहन कनेक्टिविटी:
 - हवाई संपर्क की कमी के कारण विशेषकर भूमि से घरि या भौगोलिक रूप से वंचित राज्यों में उत्पादों का प्रवाह बाधित होता है।
 - कुशल व्यापार के लिये परविहन अवसंरचना को मज़बूत करना महत्त्वपूर्ण है।
- क्लस्टर शक्ति तथा नवप्रवर्तन:
 - औद्योगिकि क्लस्टरों के लिये एक पोषण वातावरण बनाने के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि ऐसे वातावरण की कमी उत्पादकता में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
 - अनुसंधान एवं वकिस (R&D) तथा नरियात में नवप्रवर्तन पर कम फोकस को एक कमज़ोरी के रूप में देखा गया है।
- वनिरिमाण क्षेत्र एवं FDI प्रभाव:
 - महामारी का नरितर प्रभाव वनिरिमाण क्षेत्र द्वारा कम सकल मूल्यवर्द्धन तथा कई राज्यों में प्रत्यक्ष वडिशी नविश (FDI) के प्रवाह में कमी के रूप में प्रदर्शित हुआ है।
 - संघर्षरत उद्योगों को सरकारी सहायता की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- क्षमता नरिमाण तथा ज्ञान प्रसार:
 - वैश्विक स्तर पर प्रतसिपर्द्धा करने के लिये नरियातकों हेतु उचित ज्ञान प्रसार चैनलों का होना महत्त्वपूर्ण है।
 - क्षमता-नरिमाण कार्यशालाओं की अनुपस्थिति और सरकारी योजनाओं का सीमिति उपयोग नरियातकों का वैश्विक बाज़ारों में प्रवेश करने की क्षमताओं में बाधा उत्पन्न करता है।
- नरियात संकेंद्रण तथा बाज़ार में प्रवेश:
 - वविधीकरण तथा बाज़ार अनुसंधान की आवश्यकता कम संख्या में वस्तुओं एवं क्षेत्रों पर नरियात की उच्च सांद्रता के साथ-साथ इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि नरियात बहुत कम संख्या में होता है।

Overall Ranking			
Rank	State	Category	Score
1	Tamil Nadu	Coastal	80.89
2	Maharashtra	Coastal	78.20
3	Karnataka	Coastal	76.36
4	Gujarat	Coastal	73.22
5	Haryana	Landlocked	63.65
6	Telangana	Landlocked	61.36
7	Uttar Pradesh	Landlocked	61.23
8	Andhra Pradesh	Coastal	59.27
9	Uttarakhand	Himalayan	59.13
10	Punjab	Landlocked	58.95
11	Odisha	Coastal	58.84
12	Madhya Pradesh	Landlocked	55.68
13	Rajasthan	Landlocked	54.80
14	West Bengal	Coastal	53.57

सुधार के प्रमुख क्षेत्र:

- नरियात वविधिता:
 - भारत के नरियात पोर्टफोलियो में अभी भी रतन तथा आभूषण, कपड़ा एवं इंजीनियरिंग उपकरण सहित कुछ उद्योगों का अनुपातहीन रूप से

वर्चस्व है।

- उत्पादकता में सुधार के लिये देशों से नविश आकर्षण किया जा सकता है, साथ ही राज्य सरकारें नरियातकों को इन बाजारों के बारे में जानकारी तक पहुँच की सुविधा प्रदान कर सकती हैं।

■ व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत बनाना:

- कई राज्यों में व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार की आवश्यकता है, जिसमें नयामक अनुपालन लागत को कम करना तथा वित्त तक पहुँच में सुधार करना शामिल है।

■ अनुसंधान एवं विकास में नविश:

- भारत को नरियात किये जा सकने वाले नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिये अनुसंधान एवं विकास में अधिक नविश करने की आवश्यकता है।
- **प्रौद्योगिकी उन्नयन नधि योजना (TIES)** जैसी सरकारी योजनाओं का उपयोग नरियात प्रोत्साहन क्षेत्र, अनुसंधान सुविधाएँ तथा परिवहन बुनियादी ढाँचा निर्मित करने के लिये किया जा सकता है, जिससे कमज़ोर अर्थव्यवस्थाएँ मज़बूत नरियातक राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकेंगी।

■ वशिष्ट उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना:

- भारत को उन वशिष्ट उत्पादों को विकसित तथा नरियात करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जिनका मूल्य वर्द्धति है, साथ ही जो वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव के प्रति कम संवेदनशील हैं।

सुधार के लिये सफ़ारिशें:

■ क्षेत्रीय वषिमताओं को संबोधित करना:

- नरियात वृद्धि के लिये अलग-अलग राज्यों की तैयारी और क्षमता का स्तर अलग-अलग है।
 - हालाँकि नीति अपनाना महत्त्वपूर्ण है, लेकिन **इन नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकती है।**
- उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों तथा पछिड़े राज्यों के मध्य अंतर को समाप्त करने के लिये केंद्र सरकार को सबसे अधिक संघर्ष करने वाले राज्यों को सहायता प्रदान करनी चाहिये।
 - यह सहायता नरियात के लिये **आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने में सहायता के लिये वित्तपोषण, संसाधनों और विशेषज्ञता के रूप में** की जा सकती है।
- राज्यों को एक-दूसरे की सफलताओं से सीखने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिये भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
 - उदाहरणस्वरूप **हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड जैसे राज्य अन्य सफल हिमालयी राज्यों से प्रेरणा** प्राप्त कर सकते हैं।

■ भौगोलिक संकेत (GI) उत्पादों का उपयोग:

- **भौगोलिक संकेत (GI)** उत्पाद भारत के वशिष्ट क्षेत्रों के लिये अद्वितीय हैं। राज्य बाजार में मज़बूत उपस्थिति स्थापित करने के लिये इन उत्पादों का लाभ उठा सकते हैं।
 - उदाहरण के लिये **कांचीपुरम सलिक जैसे उत्पाद केवल तमिलनाडु** के लिये हैं, साथ ही इन्हें घरेलू प्रतिस्पर्धा के बिना नरियात किया जा सकता है।
 - अपने वनिरिमाण, गुणवत्ता में सुधार और वैश्विक बाजारों की पहचान करके राज्य अपना नरियात बढ़ा सकते हैं।

■ वदेश व्यापार समझौतों (FTA) का लाभ उठाना:

- भारत ने वभिन्न देशों के साथ FTA पर हस्ताक्षर किये हैं, जिससे अधिक अनुकूल व्यापारिक स्थितियाँ निर्मित हुई हैं।
 - राज्य अपने उत्पादों को साझेदार देशों की आवश्यकताओं के साथ जोड़कर तथा बाजार पहुँच को सुविधाजनक बनाकर इन समझौतों से लाभान्वित हो सकते हैं।
- नरियातक अपनी **उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिये साझेदार देशों से नविश की मांग** कर सकते हैं।

■ सटीक मूल्यांकन के लिये डेटा संग्रहण में सुधार:

- नरियात हेतु भारतीय राज्यों की तैयारियों के मूल्यांकन के लिये **सटीक और व्यापक डेटा महत्त्वपूर्ण है।**
 - डेटा संग्रहण, विशेष रूप से देश के नरियात के संबंध में, संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिये।
 - स्पष्ट डेटा लक्ष्य नीति निर्माण से क्षेत्रीय व्यापार पैटर्न को समझने में सहायता मिलती है।
- इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर सेवा नरियात और नविश पर सटीक डेटा प्राप्त करना उनके योगदान का सटीक आकलन करने के लिये आवश्यक है।